Faridabad Plot Built Properties in all Sectors

SYNDICATE ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11, Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288

Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES
(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa
24, Hours Service
Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 22 अंक 23 शुक्रवार, फरीदाबाद, 16-31 अक्टूबर, 2009 फोन : -2410196,9999595632 सहयोग राशि 1 रुपया

कानून गया भाड़ में वकील एकता ज़िन्दाबाद

इसे लोकतंत्र कहें या भीड़तंत्र?

गुडगांव (विशेष संवाददाता) दिनांक 14 अक्टूबर समय करीब 11.15 दिल्ली से गुडगांव की ओर आने वाली सड़क पर पीपल वाला चौक के पास रोज़मर्रा की तरह भारी ट्रैफ़िक जाम था। जाम में सबसे पीछे आकर खड़ी हुई एक कार नं. डी.एल.-9 सीएस-2647 में बैठे दिलबाग़ सिंह व उनकी पत्नी पूनम को सबसे पीछे खड़े रहना और अपनी बारी आने पर निकलना मंजूर नहीं था।

उन्होंने फुर्ती से अपनी गाड़ी को उल्टी दिशा यानी कि गुडगांव से दिल्ली जाने वाली सड़क पर डल दिया और जाम में सबसे आगे जाकर लगाने का प्रयास किया। उनके इस प्रयास पर जब वहां मौजूद ट्रैफ़िक सिपाही चांदराम ने रोका टोका तो कहासुनी हो गयी जो शीघ्र ही धक्का-मुक्की में बदल गयी।

इसे देखकर कुछ दूरी पर मौजूद पुलिस के अन्य सिपाही अपने साथी की मदद को आ गए। ज़्यादा सिपाहियों को आता देख दिलबाग़ ने वहां से जैसे-तैसे निकलने में ही भलाई समझी लेकिन देख लेने की धमकी ज़रूर देता गया। इससे करीब एक घंटे बाद कचहरियों के निकट स्थित सोहना रोड यानी राजीव चौक को वकीलों ने जाम कर दिया।

इसे खुलवाने पहुंचे थाना शहर व सिविल लाइन के थाना अध्यक्षों व एसीपी राजेश दुग्गल के साथ वकीलों ने धक्का-मुक्की व हाथापाई शुरू कर दी। एसीपी की गाड़ी पर लगी नीली बत्ती को तोड़कर आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर पहुंची पीसीआर नं. 17 जिप्सी के टॉयरों की हवा निकाल दी गई। पुलिस फ़ोटोग्राफर हवलदार कंवर सिंह जो सफ़ेद कपड़ों में था, बहुत बेदर्दी से मारापीटा तथा उसका कैमरा तोड़फोड़ दिया।

इससे भी खतरनाक काम यह हुआ कि सोहना रोड़ पर लगे इस जाम में पुलिस की दो गाड़ियां भी फ़ंस गयीं जो जेल से कैदियों को अदालतों में पेशी पर ले कर आती हैं। इन गाड़ियों में बैठे पुलिसवालों को जब वकीलों ने पीटना शुरू किया तो वे अपनी जान बचाकर कैदियों को राम भरोसे छोड़ कर भाग खड़े हुए। चश्मदीदों के अनुसार कुछ वकीलों ने तो उन कैदियों को मौके का फ़ायदा उठाकर भाग जाने के लिए भी उकसाया, लेकिन शुक्र यह रहा कि कोई कैदी भागा नहीं। ख़बर लिखे जाने तक पुलिस ने ट्रैफ़िक सिपाही चांद राम, फ़ोटोग्राफर कंवर सिंह, कैदियों वाली गाड़ी के ड्राइवर तथा पीसीआर-17 के ड्राइवर आदि की शिकायत पर कुल 3 मुकदमें भादसं की धारा 147, 149, 186, 332, 353, 506, 225, 228, 341 व 395 के तहत मदन सिंह चौहान, राजेन्द्र शर्मा, आनंद शर्मा, कुलदीप शर्मा, तारा चंद यादव, बाल किशन यादव व राकेश आदि के विरुद्ध दर्ज कर लिए हैं।

अब सोचने वाली बात यह है कि दसवीं पास ट्रैफ़िक सिपाही चांद राम जो नियमों व कानून की बात कर रहा था वह ग़लत था या अपने आप को पढ़ा लिखा वकील बताने वाला दिलबाग़ सिंह? यदि सिपाही चांद राम वहां न होता या वह किसी को भी न रोकता टोकता तो क्या होता? होता यह कि सभी लोग दिलबाग़ सिंह की तरह गलत साइड पर आ खड़े होते और दोनों ओर का ट्रैफ़िक ऐसा जाम हो जाता कि फ़िर सारा दिन भी न खुलता।

- **शेष पेज 2 पर**

न्यायपालिका एवं गृह मंत्रालय की सांठगांठ से

दोषी आईपीएस जेल से बाहर, पुन: ड्यूटी पर

फरीदाबाद (म.मो.) मज़दूर मोर्चा के अंक 21 में प्रकाशित हुआ था कि किस प्रकार संजय भाटिया नामक एक व्यक्ति अनुसूचित जाति के नकली प्रमाण-पत्र के आधार पर आईपीएस बन कर हरियाणा पुलिस में एसपी आ लगा।

23 वर्ष तक मुकदमा चलने के बाद उसे मात्र 100 दिन की सज़ा व दो लाख रुपये जुर्माने की सज़ा हुई थी। लेकिन बमुश्किल 15 दिन भी उसने जेल में नहीं काटे थे कि निकल कर बाहर आ गया और पुन: मधुबन (करनाल) में आ कर अपनी कुर्सी पर बैठ गया।

जैसा कि प्रकाशित किया जा चुका है कि भाटिया के वर्ष 1986 में भर्ती होते ही उसकी हेराफ़ेरी का पता चल गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वह एसपी जैसे महत्त्वपूर्ण पद पर नौकरी करता रहा तथा न्यायपालिका ने उसे सज़ा करने में 23 वर्ष लगा दिये। लेकिन यह फ़ैसला चूंकि अभी सैशन कोर्ट से हुआ था, लिहाज़ा उसे हाई कोर्ट जाने के लिए ज़मानत मिल गई जहां अपील में पांच-सात साल और लग जायेंगे। तब तक वह बाकायदा सेवानिवृत हो कर पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ भी प्राप्त कर लेगा। यदि कोई कसर रही तो समय गुज़ारने के लिये आगे सुप्रीम कोर्ट तो बाकी है ही। जानकार बताते हैं कि मामले की जानकारी मिलते ही हरियाणा सरकार ने इस अधिकारी की बर्खास्तगी के लिये केंद्रीय गृह मंत्रालय को पिछले 20 वर्षों में सैंकड़ों पत्र लिख लिये, परंतु आज तक किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं आया।

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय किसी मेले की भीड़ से कम नहीं है जहां देश भर के तमाम आईपीएस अधिकारियों के अलावा तमाम तरह के केंद्रीय सुरक्षा बलों का बही-खाता रखा जाता है।

इस काम के लिये वहां हज़ारों छोटे-बड़े बाबू बैठते हैं। बस इन्हीं में से किसी एक-दो बाबू को भाटिया ने गांठ रखा है जो मामले को आगे बढ़ने ही नहीं देता। गृह मंत्रालय का यह हाल तो तब है जब पी.चिदंबरम जैसा तथाकथित तेज़-तर्रार गृह मंत्री है, वरना इस मंत्रालय की क्या दुर्दशा होती होगी, समझना कठिन नहीं है।

माना कि आईपीएस अधिकारी को बर्खास्त करना केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ में है, परंतु उसे राज्य सरकार द्वारा निलंबित तो किया ही जा सकता है। निलंबन के बाद राज्य उस नुकसान से तो बच ही सकता है जो वह ड्यूटी पर रह कर करता आ रहा है। लेकिन राज्य सरकार ने भी कभी यह कदम उठाने की जरूरत नहीं समझी। लगता है, भाटिया ने यहां भी कोई ठीक-ठाक सी सेटिंग कर रखी है।

सरकार किसी की भी बने

जनता को क्या फायदा होगा?

मनोज कुमार झा

इस बात से आम जनता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि हरियाणा में किस दल की सरकार बनती है। जो भी सरकार बनेगी, वह या तो सांपनाथों की या नागनाथों की या फ़िर बिच्छूनाथों की होगी, जिनका एकमात्र उद्देश्य जनता को डंसना है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों के प्रत्याशियों ने आम जनता को यह कह कर बरगलाने का प्रयास किया कि 'अगर वे जीते तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे', लेकिन वे अगर चुनाव जीते तो अव्वल जनता को दर्शन ही नहीं देंगे और दिया भी तो इसके लिए काफ़ी पापड़ बेलवायेंगे। जनता का कोई काम मुफ़्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने टिकट खरीदने से लेकर चुनाव प्रचार तक में अच्छा-खासा खर्च किया है। अगर सत्ता में आने के बाद अथवा विधायक बनने के बाद ब्याज समेत वह राशि वसूल नहीं की तो फ़िर फायदा ही क्या? उम्मीदवारों में से किसी ने टिकट करोड़ों में खरीदे तो किसी का काम लाखों में ही चल गया। जग जाहिर है कि जिस पार्टी के सत्ता में आने की संभावनायें ज्यादा हैं, उसके टिकट काफ़ी महंगे बिके।

किसी ने जाति के आधार पर मोर्चा संभाला, तो किसी ने ग़रीबों में कंबल, कपड़े आदि बांट कर ही अपना वोट पक्का करने का प्रयास किया। किसी ने पूड़ी-सब्ज़ी खिला कर ग़रीबों को संतुष्ट करने का प्रयास किया तो कुछ ने शराब की बोतलें ही बांटी। साथ ही अख़बारों में विज्ञापन आदि देने में भी अच्छा-खासा खर्च किया। कुछ ने चंद पैसे देकर बच्चा ब्रिगेड ही बना लिया जिसका काम था गली-गली में उनके झंडे लेकर 'जीतेगा, भई जीतेगा' के नारे लगाना। यानी चुनाव प्रचार इस हद तक भी आ गया दुनिया का सबसे बड़ा 'लोकतंत्र' कहे जाने वाले इस देश में। जहां तक

क्या जनता इसे समझने के लिये तैयार है? यक्षप्रश्न यही है। अगर जनता सत्ता और शासन के शोषक एवं जनद्रोही स्वरूप को समझ ले तो फ़िर उसे इन चुनावों की हकीकत भी समझ में आ जायेगी। तब इन चुनावों से उसका मोहभंग हो जायेगा और वह इस बात को सोचने के लिए विवश हो जायेगी कि आखिर उसकी समस्यायें कैसे दूर हो सकती हैं।

आम जनता के हित का सवाल है, यह अनुभवसिद्ध बात है कि ऐसा किसी भी कीमत पर होने वाला नहीं। आज आम जनता लगातार बढ़ती महंगाई से तबाह है। ग़रीब आदमी को नमक के साथ पेट भर रोटी भी मिलना मुहाल हो गया है। ऐसे में लगभग हर उम्मीदवार के समर्थन में उनके स्तर के अनुरूप 'स्टार प्रचारक' आये और लोग़ों को जम कर भाषण पिलाया। लेकिन महंगाई पर रोक कैसे लगेगी, सरकारी अस्पतालों का हाल कैसे सुधरेगा, जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है, उन्हें छत मिलेगी या नहीं, ग़रीबों के बच्चे ढाबों पर बर्तन ही मांजते रहेंगे या सरकार उनके स्कूल में पढ़ने का भी बंदोबस्त करेगी, इसके बारे में भी किसी ने कुछ नहीं कहा। सरकारी महकमों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आम जनता को दिन-रात लूटने का जो अभियान चल रहा है, वह कैसे बंद होगा अथवा चलता ही रहेगा, इस संबंध में किसी भी उम्मीदवार ने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं समझी। आम लोग़ों को नेताओं ने भेड़ मान लिया है। लोग़ कहते हैं कि अरे, अभी हवा इसकी है। इसे ही वोट दे, वरना वोट बर्बाद हो जायेंगे। जिसका ज़्यादा प्रचार, जिसने अच्छा 'खिलाया-पिलाया', हवा उसी की बनती है। बहुत से लोग़ जाति के आधार पर वोट दे देते हैं। दलित होगा तो वोट इसे देगा और जाट हुआ तो उसे। यह फार्मूला वोट की राजनीति में खूब चलता है। जनता को रोटी, सिर पर छत, पानी, बिजली और चलने को सड़क चाहिए, पर यह सब उसे मिलना नहीं है, चाहे वोट किसी को दे। यहां तो रोटी के साथ पानी भी खरीद कर पीने की नौबत है। सड़कों का इतना बुरा हाल है कि थोड़ी भी बरसात हो जाये तो उस पर नाव चलाई जा सकती है। बिजली की आंख-मिचौनी चलती ही रहनी है। गत पांच वर्षों में आम जनता के हित का कोई काम नहीं हो पाया, थोथी घोषणायें बहुत हुईं। शासन ने न जाने कितनी परियोजनाओं की नींव डाली और शिलान्यास किये। पर शिलान्यास के बाद एक भी योजना पर काम शुरू नहीं हो पाया। अब चुनाव प्रचार के दौरान थोक के भाव से 'विकास' की घोषणायें फ़िर कर दी गईं।

- **शेष पेज 2 पर**